



देवभूमि के सरकारी
स्कूलों में अब 'शिक्षा
के साथ संस्कार' भी



भारत की सड़कों पर
दौड़ेगी टेस्ला, देश में
खुला पहला शोरूम

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर



वर्ष 15 | अंक 09 | मूल्य 15 रुपये | 20-26 जुलाई, 2025

धामी सरकार का विकास पर्व, "एक लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का निवेश उत्सव"



उत्तराखण्ड निवेश उत्सव



दिव्य हिमगिरि

20-26 जुलाई, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

विज्ञापन
पूनम आर्या

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता

हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम

पौड़ी: रत्नमणि भट्ट

कोटद्वार: के.पी. बौठियाल

रुद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी

चमोली: मुकेश रावत

रुड़की: श्रीगोपाल नारसन

नैनीताल: शीतल तिवारी

अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)

विकासनगर: अजय शर्मा

प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला
हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून
(उत्तराखंड)

मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164

Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर
अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क,
निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई. ई.
सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग)
देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)



वोट बटोरने का आधार बनी मुफ्त बिजली

पिछले कुछ वर्षों से देश के राजनीतिक दलों के लिए जैसे-जैसे वास्तविक मुद्दों पर आम जनता का समर्थन हासिल करना मुश्किल होता गया है, लोगों के सामने कोई सुविधा या सामान मुफ्त देने का वादा करके उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया जाने लगा है। वोट हासिल करने की मंशा से स्कूटी, टीवी या लैपटॉप या फिर कुछ राशि देना हो या फिर कोई अन्य सामान, मकसद यह होता है कि लोगों को मुफ्त मुहैया कराने का वादा किया जाए, ताकि वे मुद्दा आधारित राय बनाने की ओर ध्यान न दें। यही वजह है कि लगभग हर चुनाव के पहले जनता को कोई सुविधा मुफ्त दिलाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच एक तरह से होड़ लग जाती है। हालांकि इस तरह के चलन ने लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है और इससे लाभ-आधारित मतदान की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने के खतरे पैदा हुए हैं। यों इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सरकारी धन का उपयोग बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और विकास कार्यों में होना चाहिए, न कि चुनावों में वोट बटोरने की मंशा से मुफ्त की सौगातों पर खर्च करने के लिए। विडंबना यह है कि एक ओर सरकारें जन-कल्याण कार्यक्रमों के लिए धन जारी करने को लेकर कई तरह के बहाने बनाती रहती हैं, दूसरी ओर सत्ता में वापसी या उसे हासिल करने के लिए व्यापक पैमाने पर मुफ्त की कोई सुविधा मुहैया कराने के वादे किए जाते हैं। एक तरह से यह जनता को दिया जाने वाला लालच है, जिसके जरिए बुनियादी सुविधाओं और अन्य जरूरी मुद्दों पर पर्दा डाला जाता है। हाल के वर्षों में चुनावों में जीत हासिल करने के लिए अमूमन हर पार्टी ने इस मुफ्त के औजार का इस्तेमाल किया है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अब इसका अपवाद नहीं है। गौरतलब है कि गुरुवार को बिहार सरकार ने आम घरेलू उपभोक्ताओं को एक सौ पच्चीस यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। यह फैसला अगले महीने से लागू हो जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी थी। जाहिर है, बिहार में इस तरह की घोषणाओं की पृष्ठभूमि में अगले कुछ महीने के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। हालांकि बिजली मुफ्त मुहैया कराने के मसले पर नीतीश कुमार की राय अलग थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब उन्हें भी जनता के सामने मुफ्त की रेवडियों का सपना दिखाने में कोई हिचक नहीं हो रही। आखिर क्या कारण है कि बिहार सहित देश भर में जहां भी इस तरह के मुफ्त की सौगात जनता को देने के वादे किए जाते हैं, उनका समय हर बार चुनाव से पहले का वक्त होता है! सड़क, शिक्षा-व्यवस्था, रोजगार आदि के मसले पर खर्च का सवाल आते ही धन की कमी का रोना वाली सरकारों को अपने अधिकार के क्षेत्र के सभी लोगों के लिए किसी सुविधा को मुफ्त करने का वादा करने में कोई हिचक नहीं होती। जबकि अगर न्यायपूर्ण आय और उचित खर्च के स्तर को बनाए रखा जाए, रोजगार के सवाल पर ईमानदार इच्छाशक्ति से काम किया जाए, तो लोगों की क्रयशक्ति को इतना मजबूत जरूर बनाया जा सकता है कि उन्हें मुफ्त सौगात की जरूरत नहीं पड़े। अफसोस यह भी है कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के बजाय सरकारें उनमें परनिर्भरता की आदत डालने में ज्यादा रुचि दिखा रही हैं। इस क्रम में जनकल्याण की जिम्मेदारी के तहत किए जाने वाले कार्यों और मुफ्त की रेवडियों में फर्क मिटाने की कोशिश की जा रही है।

कुँवर राज अस्थाना

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तराखंड का निराशाजनक प्रदर्शन: अनूप नौटियाल

स्वच्छ भारत मिशन के दस साल बाद भी राष्ट्रीय रैंकिंग में एक भी शहर नहीं



स्वच्छ भारत मिशन के दस वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उत्तराखंड एक भी प्रमुख पुरस्कार श्रेणी में स्थान नहीं बना सका है। यह

जानकारी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार समारोह में सामने आई, जहां पूरे देश में साफ सफाई के बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया गया।

उत्तराखंड के लालकुआं नगर को 'प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर-राज्य श्रेणी' में स्थान मिला है किन्तु देहरादून स्थित पर्यावरण गीय एक्शन और एडवोकेसी समूह एसडीसी फाउंडेशन ने इसे प्रत्येक राज्य से एक शहर को नामांकित करने की अनिवार्यता के तहत दिया गया प्रतीकात्मक पुरस्कार बताया है, न कि किसी वास्तविक प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन का परिणाम।

एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने कहा कि यह आत्मचिंतन का अवसर है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य लगातार राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड लगातार गायब है। यह किसी एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के सिस्टम की उदासीनता और राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्राथमिकता की कमी का

परिणाम है।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत देशभर के शहरों को पाँच जनसंख्या श्रेणियों में विभाजित कर सम्मानित किया गया जिसमें 10 लाख से अधिक, 3-10 लाख, 50,000-3 लाख, 20,000-50,000 और 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहर शामिल हुए। उन्होंने दुख जताया कि जहां इंदौर, सूरत, नोएडा, चंडीगढ़, लखनऊ, उज्जैन, मैसूर, अंबिकापुर, तिरुपति और लोनावला जैसे कई अन्य शहर लगातार मिसाल पेश कर रहे हैं, वहीं देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, हल्द्वानी और उत्तराखंड के अन्य सभी शहर लगातार सूची से बाहर हैं।

एसडीसी फाउंडेशन, जो पिछले कई वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजों का विश्लेषण उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कर रहा है ने दीर्घकालिक और संस्थागत सुधारों की अपनी सिफारिशें दोहराईं। अनूप नौटियाल ने कहा कि हम बार-बार कह चुके हैं कि दिखावे का प्रयास और फोटो सेशन से उत्तराखंड को कोई लाभ नहीं होगा। यदि हमारे बड़े शहर जो 3 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं लगातार असफल हो रहे हैं, तो कम से कम राज्य को 50,000-3 लाख, 20,000-50,000 या 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में एक मॉडल आदर्श स्वच्छ नगर विकसित करने का गंभीर प्रयास करना चाहिए।

इस समन्वय और जवाबदेही के संकट को दूर करने के लिए उन्होंने एक स्वतंत्र 'वेस्ट मैनेजमेंट कमीशन (कचरा प्रबंधन आयोग)' गठित करने की मांग को फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि समग्र कचरा प्रबंधन किसी एक विभाग का काम नहीं है। इसमें शहरी निकाय, शहरी विकास विभाग, पंचायती राज, वन विभाग, पर्यटन, पेयजल निगम, जल संस्थान और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित कई विभाग शामिल हैं। भारत सरकार ने भी 2016 में प्लास्टिक, ठोस कचरा, ई-कचरा, बायोमैडिकल, खतरनाक और निर्माण व ध्वस्तीकरण कचरे को लेकर छह अलग अलग कानून बनाए थे।

अनूप ने कहा कि वर्तमान प्रशासनिक ढांचा जिसमें समितियाँ, मुख्य सचिव, आयुक्त, डीएम, नगर निकाय और अनेकों



अधिकारी शामिल हैं वो प्रदेश के 13 जिलों के 95 ब्लॉकों और 53,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले उत्तराखंड में इन सभी छह कचरा धाराओं का समन्वित दैनिक प्रबंधन करने में असमर्थ है।

उन्होंने कहा कि राज्य में हर साल 8 से 10 करोड़ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के आने का अनुमान है, जो आने वाले वर्षों में और बढ़ेगा।

अनूप ने मांग की कि जब उत्तराखंड राज्य में पलायन आयोग बन सकता है, तो राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट कमीशन क्यों नहीं बन सकता? उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आयोग स्वतंत्र होना चाहिए, न कि राजनीतिक नियुक्तियों या सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए एक और पदस्थापन का केंद्र। इसकी अगुवाई कचरा प्रबंधन के विशेषज्ञ को दी जानी चाहिए, जिसे राज्य मंत्री या कैबिनेट स्तर की जिम्मेदारी, अधिकार और बजट मिले।

अनूप ने दोहराया कि कचरा प्रबंधन कोई हल्का विषय नहीं है। यह उत्तराखंड जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील राज्य के लिए सबसे जटिल, गंभीर और प्रभावशाली मुद्दों में से एक है। जब तक हम अपनी नीतियों और व्यवस्थाओं में संस्थागत और व्यापक सुधार नहीं लाएंगे, तब तक हमारे शहर और गाँव राष्ट्रीय मानकों से पिछड़ते रहेंगे और आम नागरिकों और पर्यटकों को इसकी कीमत बीमारियों, पर्यावरण क्षरण, आर्थिक अवसरों की कमी और प्रशासनिक उदासीनता के रूप में चुकानी पड़ेगी,' उन्होंने कहा।

धामी सरकार के चलाए गए 'ऑपरेशन कालनेमि' को देवभूमि में खूब सराहा



उत्तराखंड की धामी सरकार के चलाए गए 'ऑपरेशन कालनेमि' सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति बन गया है। सरकार की इस पहल ने न केवल फर्जी बाबाओं की दुकानों पर ताले लगाए, बल्कि आस्था के नाम पर चल रही ठगी, शोषण और अंध विश्वास की जड़ों पर भी करारा प्रहार किया। गांव-गांव में अब झाड़ू-फूंक की जगह तर्क की आवाज सुनाई देने लगी है। महिलाएं खुलकर कह रही हैं, 'अब नहीं डरेंगे', और युवा वर्ग विज्ञान और विवेक की राह पर आगे बढ़ रहा है। यह केवल कानून की कार्रवाई नहीं थी, यह चेतना की वह मशाल थी जिसने उत्तराखंड को जागरूकता का नया मंत्र दे दिया ऑपरेशन कालनेमि। मुख्यमंत्री धामी के चलाए गए इस ऑपरेशन कालनेमि को सोशल मीडिया पर जमकर सराहा गया। उत्तराखंड की पुण्यभूमि पर किसी भी प्रकार का ढोंग, छल या धार्मिक आवरण में छिपा अपराध सहन नहीं किया जाएगा। धार्मिक चोला पहन कर आम लोगों को ठगने वाले फर्जी बाबाओं और ढोंगियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस विशेष अभियान को सोशल मीडिया साइट एक्स पर #OperationKaalnemi पर व्यापक समर्थन मिला। यह ट्रेंड कई घंटों तक टॉप में बना रहा। शंभू नाथ गौतम।

इसी महीने 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा को उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश में 'ऑपरेशन कालनेमि' चलाकर अभी तक 100 से अधिक पाखंडी बाबाओं को सलाखों के पीछे भेजा है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री धामी के चलाए गए इस ऑपरेशन कालनेमि को जमकर सराहा गया। उत्तराखंड की पुण्यभूमि पर किसी भी प्रकार का ढोंग, छल या धार्मिक आवरण में छिपा अपराध सहन नहीं किया जाएगा। धार्मिक चोला पहन कर आम लोगों को ठगने वाले फर्जी बाबाओं और ढोंगियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस विशेष अभियान को सोशल मीडिया साइट एक्स पर #OperationKaalnemi पर व्यापक समर्थन मिला। यह ट्रेंड कई घंटों तक टॉप में बना रहा। लोगों ने सोशल मीडिया पर सीएम धामी की निडरता और त्वरित कार्रवाई की जमकर सराहना की। कई यूजर्स ने उन्हें 'सनातन धर्म का प्रहरी', 'धर्म और श्रद्धा का रक्षक' तक कह डाला। वहीं, कई राज्यों के लोगों ने भी इस तरह की कार्यवाही की अपने राज्यों में भी मांग की है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस ऑपरेशन ने देश के जनमानस में गहरी छाप छोड़ी है। सोमवार को जैसे ही यह ट्रेंड शुरू हुआ, घंटों तक #OperationKaalnemi टॉप ट्रेंडिंग में बना रहा। ये दर्शाता है कि अब जनता सिर्फ आस्था के नाम पर दिखावे से नहीं, वास्तविक धर्म और संस्कारों की रक्षा चाहती है, और मुख्यमंत्री धामी इस दिशा में एक आदर्श नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे हैं। इससे पहले भी सीएम धामी धर्म और सनातन की रक्षा के लिए थूक, लव, लैंड जिहाद पर कार्रवाई के साथ ही धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई

कर चुके हैं। जिससे पूरे देश में उनकी धर्मरक्षक की छवि बनकर ऊभरी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विशेष अभियान की शुरुआत की थी। जिसका उद्देश्य था, उत्तराखंड में सक्रिय ऐसे लोगों की पहचान और गिरफ्तारी होगी जो साधु-संत का भेष धारण कर धार्मिक स्थलों पर ठगी या अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त हैं।

धामी सरकार की अंधविश्वास के अंधेरे में रोशनी की एक किरण बना ऑपरेशन कालनेमि

उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा शुरू किए गए 'ऑपरेशन कालनेमि' का उद्देश्य सिर्फ फर्जी बाबाओं का पर्दाफाश करना नहीं था, बल्कि समाज में तेजी से फैलते अंधविश्वास, ढोंग और धार्मिक ठगी के उस गहरे जाल को काटना भी था जिसमें मासूम लोग फंसे चले जा रहे थे।

जब सरकार ने इस ऑपरेशन की शुरुआत की, तो शुरुआत में इसे राजनीतिक स्टंट तक कहा गया। लेकिन जैसे-जैसे पाखंडी बाबाओं की लिस्ट सामने आती गई और उनपर सख्त एक्शन लिए गए, आम लोगों का भरोसा और समर्थन बढ़ता गया। पहाड़ों में बसे भोले-भाले ग्रामीणों को जब यह पता चला कि अब उनके विश्वास का शोषण करने वालों पर कानून की नजर है, तो उन्होंने भी खुलकर समर्थन देना शुरू किया। टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे दूरस्थ इलाकों से ऐसी खबरें सामने आने लगीं कि लोग अब इन फर्जी बाबाओं की शिकायतें सीधे प्रशासन को कर रहे हैं। कहीं एक बाबा की गुफा से करोड़ों का चढ़ावा बरामद हुआ, तो कहीं किसी बाबा के डेरे से नशीली दवाएं और हथियार तक मिले। सबसे ज्यादा असर उन महिलाओं पर पड़ा जो अब तक झाड़ू-फूंक और तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी और शोषण सह रही थीं। ऑपरेशन कालनेमि के बाद वे अब खुलकर बोल रही हैं, अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचा रही हैं। इस ऑपरेशन के बाद युवाओं में जागरूकता की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर #OperationKaalnemi ट्रेंड करता रहा और कई छात्रों-नौजवानों ने फर्जी बाबाओं के खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दिया। ऑपरेशन कालनेमि सिर्फ कानून का कदम नहीं था, यह सामाजिक चेतना का बिगुल था। यही कारण है कि इसे सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सुधार आंदोलन माना जा रहा है। उत्तराखंड की यह पहल अब एक मॉडल बन रही है, जिसे देश के अन्य राज्य भी अपनाने की सोचने लगे हैं।

भारत की सड़कों पर दौड़ेगी टेस्ला, देश में खुला पहला शोरूम



दो प्रमुख मॉडल मॉडल 3 और मॉडल वाई को प्रदर्शित किया गया है। टेस्ला शोरूम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से डिजिटल ग्राहक अनुभव पर आधारित है। ग्राहक बिना किसी कागजी प्रक्रिया के कार की बुकिंग कर सकते हैं और सारी जानकारी डिजिटल रूप में प्राप्त कर सकते हैं।

भारत में इलेक्ट्रिक व्हनों पर फर्राटा भरने वालों के लिए 15 जुलाई का दिन खुशियां लेकर आया। महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में दुनिया के सबसे रईस बिजनेसमैन एलन मस्क ने टेस्ला का पहला शोरूम की ओपनिंग की। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) के क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया की सबसे चर्चित और अग्रणी ईवी निर्माता कंपनी टेस्ला ने आखिरकार भारतीय बाजार में कदम रख दिया है। कंपनी ने अपना पहला आधिकारिक शोरूम मुंबई में खोलकर इस यात्रा की शुरुआत की है। इस कदम से न केवल टेस्ला के प्रशंसकों में उत्साह की लहर दौड़ गई है, बल्कि भारत के ऑटो सेक्टर में भी हलचल मच गई है। मुंबई के पॉश इलाके में खुले इस शोरूम को टेस्ला की पहचान के अनुरूप फ्यूचरिस्टिक और हाईटेक तरीके से डिजाइन किया गया है। यहां ग्राहकों को वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस, इंटेक्टिव डिस्प्ले, और टेस्ट ड्राइव की सुविधाएं मिलेंगी। टेस्ला शोरूम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पूरी तरह से डिजिटल ग्राहक अनुभव पर आधारित है। ग्राहक बिना किसी कागजी प्रक्रिया के कार की बुकिंग कर सकते हैं और सारी जानकारी

दुनिया के सबसे रईस बिजनेसमैन एलन मस्क ने मुंबई में टेस्ला का पहला हाईटेक शोरूम खोल दिया है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति ने एक नया मोड़ ले लिया है। दुनिया की सबसे चर्चित ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक टेस्ला ने आखिरकार भारतीय बाजार में औपचारिक एंट्री कर ली है। कंपनी ने देश में अपना पहला शोरूम खोलकर यह साफ कर दिया है कि अब भारत भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। एलन मस्क की यह हाईटेक कार कंपनी अब भारतीय सड़कों पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने को तैयार है, और ग्राहक इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शोरूम में फिलहाल टेस्ला की

डिजिटल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। शोरूम की आंतरिक सज्जा, लाइटिंग और प्रेजेंटेशन एक प्रिमियम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देती है। एलन मस्क पहले ही संकेत दे चुके हैं कि भारत उनके लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा था कि 'टेस्ला जल्द ही भारत में दस्तक देगी।' अब जब कंपनी ने भारत में अपना पहला शोरूम खोल दिया है, तो आने वाले वर्षों में टेस्ला की भारत में मैनुफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना भी जमीन पर उतर सकती है। टेस्ला भारत में सिर्फ कारें बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहती। कंपनी देशभर में सुपरचार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि टेस्ला यूजर्स को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान चार्जिंग की चिंता न हो। कंपनी की नजर देश के महानगरों से लेकर दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक अपनी पहुंच बनाने पर है। जैसे ही शोरूम खुला, टेस्ला फैंस और ऑटोमोबाइल प्रेमियों ने शोरूम की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की।

सीमा शुल्क और माल ढुलाई की लागत की वजह से भारत में टेस्ला की कार महंगी- भारत में टेस्ला की कार महंगी बिकने के दो

कारण हैं। पहला सीमा शुल्क और दूसरा माल ढुलाई की लागत। भारत में इस समय टेस्ला की कोई विनिर्माण इकाई नहीं है। विदेशों से पूरी तरह तैयार होकर यह कार भारत आ रही है, इसलिए कंपनी के लिए लागत काफी बढ़ गई है। रिपोर्टों के अनुसार, टेस्ला ने भारत में मॉडल वाई पिछले पहिए से चलने वाली स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन के पहले बैच को अपने चीन स्थित संयंत्र से मंगवाया है। टेस्ला इस समय भारत में अपना मॉडल वाई लेकर आई है। भारत में इसके प्रवेश स्तर के पिछले पहिए से चलने वाले संस्करण की कीमत 59.89 लाख रुपये है। इसकी सड़क पर कीमत 61.07 लाख रुपये है। वहीं, लंबी दूरी वाले संस्करण की कीमत 67.89 लाख रुपये है। इसकी सड़क पर कीमत 69.15 लाख रुपये है। टेस्ला ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि वह कार की आपूर्ति शुरू होने से पहले भारत में तीव्र चार्जिंग केंद्र लगाएगा। भारत में टेस्ला मॉडल वाई पिछले पहिए से चलने वाला संस्करण दो बैटरी संयोजनों के साथ आ रहा है। एक 60 किलोवॉट-घंटा बैटरी के साथ और दूसरा 75 किलोवॉट-घंटा बैटरी के साथ आ रहा है। यह मॉडल एकल विद्युत मोटर के साथ आता है, जो 295 अश्वशक्ति उत्पन्न करती है। रिपोर्टों के अनुसार, 60 किलोवॉट-घंटा बैटरी वाली कार पूर्ण चार्ज पर 500 किलोमीटर की डब्ल्यूएलटीपी दूरी तय करती है, जबकि 75 किलोवॉट-घंटा बैटरी वाला संस्करण 622 किलोमीटर की दूरी का दावा करता है। भारत में टेस्ला का मॉडल वाई 7 विभिन्न रंगों में उपलब्ध है। साथ ही 2 आंतरिक सजावट विकल्प भी उपलब्ध हैं। इस कार में आगे की ओर 15.4 इंच की जानकारी और मनोरंजन स्क्रीन मिल रही है। पीछे के यात्रियों के लिए 8 इंच की प्रदर्शनी स्क्रीन मिल रही है। इसके अलावा, बिजली से समायोजित होने वाली आगे की सीटें, दो क्षेत्रों वाला तापमान नियंत्रण तंत्र, 19 इंच के क्रॉसफ्लो पहिए और एक स्थायी कांच की छत जैसे सुविधाएं भी इस कार में मिल रही हैं। बता दें कि कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड भारत में टेस्ला का पहला फाइनेंसर होगा। इस पार्टनरशिप के तहत ग्राहक टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों के लिए खासतौर पर तैयार किए गए फाइनेंस ऑप्शंस के बारे में जानकारी टेस्ला की इंडियन वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए लगा सकते हैं। टेस्ला की इंडिया में एंट्री के बाद ईवी सेगमेंट में काफी बज क्रीएट हो चुका है। हालांकि टेस्ला की कीमतों के बारे में भारत में खूब चर्चा हो रही है, इस कदम को भारत के ईवी क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।



धामी सरकार का विकास पर्व, "एक लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का निवेश उत्सव"



शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखण्ड की औद्योगिक नगरी रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार, 19 जुलाई साल 2025 को इतिहास रच दिया। एक लाख करोड़ रुपये की ग्राउंडिंग के साथ धामी सरकार ने 'निवेश उत्सव' का भव्य आयोजन कर

विकास की नई गूंज बिखेरी। सम्पन्न हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता कर प्रदेश को औद्योगिक उड़ान देने का संकल्प दोहराया। निवेश उत्सव के रूप में आयोजित इस मेगा इवेंट में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री धामी ने भाग लेकर प्रदेश को औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर करने का संदेश दिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम धामी के कार्यों को भी जमकर सराहा। इस आयोजन के माध्यम से उन निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारा गया, जिनके एमओयू ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हस्ताक्षरित हुए थे। रुद्रपुर में हुई ग्राउंडिंग के जरिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं वास्तविक रूप ले रही हैं, जिनसे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

देवभूमि उत्तराखण्ड की औद्योगिक नगरी रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुक्रवार, 19 जुलाई साल 2025 को इतिहास रच दिया। एक लाख करोड़ रुपये की ग्राउंडिंग के साथ धामी सरकार ने निवेश उत्सव का भव्य आयोजन कर विकास की नई गूंज बिखेरी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहभागिता कर प्रदेश को औद्योगिक उड़ान देने का संकल्प दोहराया। यह निवेश उत्सव धामी सरकार की बड़ी उपलब्धियां में से एक है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आयोजित एक लाख करोड़ रुपये के निवेश की ग्राउंडिंग समारोह में विकास की नई लहर स्पष्ट दिखी। 'निवेश उत्सव' के रूप में आयोजित इस मेगा इवेंट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लेकर प्रदेश को औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर करने का संदेश दिया। साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। इन्वेस्टर्स समिट ग्राउंडिंग सेरेमनी को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड

की जमकर तारीफ की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम धामी के कार्यों को भी जमकर सराहा। इस आयोजन के माध्यम से उन निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारा गया, जिनके एमओयू ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हस्ताक्षरित हुए थे। रुद्रपुर में हुई ग्राउंडिंग के जरिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं वास्तविक रूप ले रही हैं, जिनसे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 'उत्तराखण्ड अब निवेश के लिए तेजी से उभरता हब बन रहा है। जो निवेश पहले कागजों पर था, अब वह धरातल पर उतर रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन की दिशा में प्रदेश का ठोस कदम है।

निवेश उत्सव सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की नींव है: अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निवेश उत्सव कार्यक्रम में कहा कि उत्तराखण्ड में यह निवेश उत्सव केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। धामी

जी की अगुवाई में राज्य तेजी से औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने यह भी जोड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देशभर में जो परिवर्तन लाया जा रहा है, उत्तराखंड उसका उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को निवेश-मित्र प्रदेश बना रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रुद्रपुर में शुरू हुई ग्राउंडिंग समारोह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रदेश को औद्योगिक विंग देने का स्वागत है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में नए रोजगार के द्वार खुलेंगे, जिससे राज्य की युवा शक्ति का भंडार सशक्त होगा। गृहमंत्री अमित शाह कहा कि यह निवेश सिर्फ जितना जरूरी है, उसके साथ पर्यावरणीय हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने माना कि यह कार्यक्रम उन सभी एमओयू को जमीन पर उतारने का महत्वपूर्ण पर्व है, जिनका हस्ताक्षर 2023 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुआ था। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच 'विकसित भारत' के अनुरूप राज्य सरकार ने तेजी से कार्रवाई की है। उत्तराखंड अब केवल पहाड़ की खूबसूरती से नहीं, बल्कि औद्योगिक शक्ति से भी जाना जाएगा। अमित शाह ने कहा जब प्रदेशवासी उत्तराखंड बनाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे तब कांग्रेस ने उत्तराखण्ड के आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया। उत्तराखंड को बनाने का काम भाजपा के नेताओं और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अमित शाह ने कहा अटल जी देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे और मोदी जी 10 साल में इस अर्थव्यवस्था को चौथे नंबर पर लेकर आए। 2027 में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

निवेशक अब उत्तराखंड में पूरे भरोसे के साथ निवेश करने आ रहे: सीएम धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि निवेशक अब उत्तराखंड में पूरे भरोसे के साथ आ रहे हैं। राज्य सरकार ने ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और तेज भूमि आवंटन जैसी नीतियों के जरिए औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाया है। उन्होंने बताया कि जिन परियोजनाओं पर आज से काम शुरू हो रहा है, वे सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि राज्य की आर्थिक रीढ़ भी बनेंगी। कार्यक्रम में



डॉ सुनील राय

अध्यक्ष, यूपीईएस

यूपीईएस शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉ सुनील राय ने कहा कि उत्तराखंड के ज्यादातर शिक्षण संस्थान, किसी ना किसी संस्था से मान्यता प्राप्त हैं, इससे यहां शिक्षण की गुणवत्ता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि उनका संस्थान, उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर राज्य के विकास में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब कनेक्टिविटी काफी सुधारी गई है, इससे यहां निवेश के अवसर और भी लाभप्रद हो जाते हैं। राज्य में 10 से अधिक रिसर्च संस्थान होने से भी, शिक्षण संस्थानों को इसका फायदा मिलता है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मंच पर मौजूद रहे। उन्होंने इसे मोदी-धामी युग की औद्योगिक क्रांति बताते हुए कहा कि उत्तराखंड को 'औद्योगिक तीर्थ' बनाने की दिशा में यह मजबूत कदम है। इस मौके पर योगगुरु बाबा रामदेव भी कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने पतंजलि की ओर से राज्य में निवेश को और आगे बढ़ाने की बात कही। बाबा रामदेव ने उत्तराखंड को योग और स्वदेशी उद्योग की धरती बताते हुए युवाओं से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। इसके अलावा प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जैसे मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आदि भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड और सिडकुल से जुड़े अधिकारी भी निवेशकों को मंच से प्रेजेंटेशन देते दिखे। उद्योग जगत से टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, पतंजलि, हीरो इलेक्ट्रिक, ग्रीनको, आईटीसी और जेएसडब्ल्यू जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति दर्ज की गई। कई स्थानीय और राष्ट्रीय स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर से जुड़े उद्यमियों ने भी

इसमें भाग लिया। इन सभी निवेशकों की परियोजनाएं अब उत्तराखंड में जमीन पर उतरेंगी, जिनमें उत्पादन इकाइयां, लॉजिस्टिक्स पार्क, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट और फार्मा प्लांट शामिल रहे।

उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में निवेश उत्सव एक बड़ा कदम यह निवेश महोत्सव राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस कार्यक्रम को साल 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, जहां अनेक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अब इन समझौतों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया इस ग्राउंडिंग सेरेमनी के साथ शुरू हो गई। इस समारोह में देश के प्रमुख उद्योगपतियों, व्यवसायिक नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों की नई स्थापित इकाइयों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति रहे। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर यह भी कहा कि सरकार निवेशकों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस, तेजी से भूमि आवंटन, और पर्यावरण संतुलन के साथ विकास जैसी सुविधाएं दे रही है। साथ ही, युवा उद्यमियों को भी स्टार्टअप्स के लिए हर संभव सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार निवेशकों को हरसंभव सहायता दे रही है, जिसमें तेज मंजूरी की प्रक्रिया, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और शांतिपूर्ण व उद्योग-अनुकूल वातावरण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब निवेशकों की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है, जिसका श्रेय राज्य की स्थिर सरकार, कुशल मानव संसाधन और प्राकृतिक विशेषताओं को जाता है। सीएम धामी ने बताया कि निवेश की प्रतिबद्धताओं को अब जमीनी परियोजनाओं में बदला जा रहा है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल औद्योगिक परियोजनाओं की शुरुआत करना ही नहीं है, बल्कि देश-विदेश के निवेशकों को यह स्पष्ट संदेश देना है कि उत्तराखंड निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कार्यक्रम उत्तराखंड को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और रोजगार सृजन की दिशा में एक निर्णायक कदम है। रुद्रपुर में सम्पन्न यह आयोजन केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं था, बल्कि यह संकेत है कि उत्तराखंड अब देश की निवेश राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। धामी सरकार की सक्रिय नीति और केंद्र सरकार का सहयोग राज्य के युवाओं, उद्यमियों और उद्योगों के लिए सुनहरा भविष्य लेकर आ रहा है।

विकार त्याग कर ही बन सकते है सच्चे शिवभक्त!



डॉ श्रीगोपाल नारसन
एडवोकेट

यह कैसी शिव की भक्ति है
हिंसा में आसक्ति है
भगवा पहनकर भी तन पर
विकार ग्रसित प्रवृत्ति है
शिव पूजा अगर मकसद है
कांवड़ ले जाना सद्कर्म है
गंगा जल से निर्मल स्वयं बनो
शिव भक्ति शांत भाव से करो
लाठी-डंडो का त्याग करो
डीजे का बहिष्कार करो
जो व्यवस्था बनी उस पर चलो
धैर्य गुण आत्मसात करो
शिव सहज ही खुश होंगे
जलाभिषेक स्वीकार करेंगे
ऐसा हो तो वंदन होगा
जगह-जगह अभिनन्दन होगा
बम-बम भोले जयघोष करेंगे
इंसान से फिर देवता बनेंगे।

सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि मनाई जाती है। यह दिन भगवान शिव की भव्य पूजा को समर्पित है। इस दिन महादेव केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। सावन शिवरात्रि पर उपवास रखना और भी शुभ होता है। इसके प्रभाव से साधक को धन लाभ, सुख-समृद्धि और यश-कीर्ति की प्राप्ति होती है। सावन की शिवरात्रि को शिव-पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस दिन की गई उपासना से प्रेम जीवन सुखमय और मनचाहा वर पाने की कामना पूर्ण होती है। इस साल 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि है। इस बार शिवरात्रि पर भद्रा का साया बना हुआ है।

सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 23 जुलाई, प्रातः 04:39 मिनट पर आरंभ होकर 24 जुलाई, देर रात 02:28 मिनट पर समाप्त होगी। इसलिए 23 जुलाई को ही शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार सावन शिवरात्रि पर भद्रा सुबह 05 बजकर 37 मिनट से दोपहर 03 बजकर 31 मिनट तक रहेगी। वास्तव में परम-आत्मा का नाम ही शिव है, जिसका संस्कृत अर्थ है 'सदा कल्याणकारी', अर्थात् वो जो सभी का कल्याण करता है। शिवरात्रि व शिवजयन्ती भारत में द्वापर युग से मनाई जाती है। यह दिन हम ईश्वर के इस धरा पर अवतरण के समय की याद में मनाते हैं। शिव के अलावा ओर किसी को भी हम

'परम-आत्मा' नहीं कहते। शिव के साथ रात शब्द इसलिए जुड़ा है क्योंकि वो अज्ञान की अँधेरी रात में इस सृष्टि पर आते हैं। जब सारा संसार, मनुष्य मात्र अज्ञान रात्रि में, अर्थात् माया के वश हो जाता है, जब सभी आत्माएं 5 विकारों के प्रभाव से पतित हो जाती हैं, जब पवित्रता और शान्ति का सत्य धर्म व स्वम् की आत्मिक सत्य पहचान हम भूल जाते हैं। सिर्फ ऐसे समय पर, हमें जगाने, समस्त मानवता के उत्थान व सम्पूर्ण विश्व में फिर से शान्ति, पवित्रता और प्रेम का सत-धर्म स्थापित करने परमात्मा एक साधारण शरीर में प्रवेश करते हैं।

भगवत गीता में यह श्लोक है जो इसे दर्शाता है:

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः।
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥
परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मं संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥

परमात्मा पिता का हम बच्चों से यह वायदा है कि जब-जब धर्म की अति ग्लानि होगी, सृष्टि पर पाप व अन्याय बढ़ जायेगा... तब वे इस धरा पर अवतरित होंगे... अब हमने जाना है की वो एक साधारण मनुष्य तन का आधार लें, हमें सत्य ज्ञान सुनाकर, सद्गति का रास्ता दिखा, दुःखों से मुक्त कर रहे हैं। यह गायन वर्तमान समय का ही है, जबकि कलियुग के अन्त और नई सृष्टि

सतयुग के संगम पर, स्वयं परमात्मा अपने वायदे अनुसार इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं, तथा इस दुःखमय संसार (नर्क) को सुखमय संसार ढ़स्वर्गत्र में परिवर्तन करने का महान कार्य गुप्त रूप में करा रहे हैं। महाशिवरात्रि के साथ जुड़े हुए आध्यात्मिक महत्व को समझने का ये सबसे अच्छा अवसर है। शिव-लिंग परमात्मा शिव के ज्योति रूप को दर्शाता है। परमात्मा का कोई मनुष्य रूप नहीं है और ना ही उसके पास कोई शारीरिक आकार है। भगवान शिव एक सूक्ष्म, पवित्र व स्वदीप्तिमान दिव्य ज्योति पुंज हैं। इस ज्योति को एक अंडाकार रूप से दर्शाया गया है। इसीलिए उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में दिखाया गया है, अर्थात् 'ज्योति का प्रतीक'। वो सत्य है, कल्याणकारी हैं और सबसे सुंदर आत्मा है, तभी उन्हें सत्यम-शिवम्-सुंदरम् कहा जाता है। वो सत-चित्त-आनंद स्वरूप भी है।

वास्तव में जो परम ऐश्वर्यवान हो, जिसे लोग भजते हो अर्थात् जिसका स्मरण करते हो एक रचता के रूप में, एक परमशक्ति के रूप में, एक परमपिता के रूप में, वही ईश्वर है और वही शिव है। एक मात्र वह शिव जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी रचयिता है। शिव जीवन मरण से परे है। ज्योति बिन्दू स्वरूप है। वास्तव में शिव एक ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण मात्र से परमात्मा की सुखद अनुभूति होने लगती है। शिव को कल्याणकारी तो सभी मानते हैं, साथ ही शिव ही सत्य है शिव ही सुन्दर है, यह भी सभी स्वीकारते हैं। परन्तु यदि मनुष्य को शिव का बोध हो जाए तो उसे जीवन मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म के मार्ग से लोग विचलित हो जाते हैं, समाज में अनाचार, पापाचार, अत्याचार, शोषण, क्रोध, वैमनस्य, आलस्य, लोभ, अहंकार, कामुकता, माया मोह बढ़ जाता है, तब तब ही परमात्मा को स्वयं आकर राह भटके लोगो को सन्मार्ग पर लाने की प्रेरणा का कार्य करना पड़ता है। ऐसा हर पांच हजार साल में पुनरावृत्त होता है। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलियुग और फिर संगम युग तक की यात्रा इन पांच हजार वर्षों में होती है। हांलाकि सतयुग में हर कोई पवित्र, सस्कारवान, चिन्तामुक्त और सुखमय होता है। परन्तु जैसे जैसे सतयुग से त्रेता और त्रेता से द्वापर तथा द्वापर से कलियुग तक का कालचक्र घूमता है। वैसे वैसे व्यक्ति रूप में मौजूद आत्मायें भी शान्त, पवित्र और सुखमय से अशान्त, दुषित और दुःखमय हो जाती है। कलियुग को तो कहा

ही गया है दुखों का काल। लेकिन जब कलियुग के अन्त में संगम युग से सतयुग के आगमन की घड़ी आती है तो यही वह समय जब परमात्मा स्वयं सतयुग की दुनिया बनाने के लिए आत्माओं को पवित्र और पावनता का स्वयं ज्ञान देते हैं और आत्माओं को सतयुग के काबिल बनाते हैं।

समस्त देवी देवताओं में मात्र शिव ही ऐसे देव हैं जो देवों के देव यानि महादेव हैं जिन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। परमात्मा शिव ही निराकारी और ज्योति स्वरूप है जिसे ज्योति बिन्दू रूप में स्वीकारा गया है। परमात्मा सर्व आत्माओं से न्यारा और प्यारा है जो देह से परे है जिसका जन्म मरण नहीं होता और जो परमधाम का वासी है और जो समस्त संसार का पोषक है। दुनियाभर में ज्योतिर्लिंग के रूप में परमात्मा शिव की पूजा अर्चना और साधना की जाती है। शिवलिंग को ही ज्योतिर्लिंग के रूप में परमात्मा का स्मृति स्वरूप माना गया है। संसार में सबसे पहले सोमनाथ के मन्दिर में हीरे कोहिनूर से बने शिवलिंग की स्थापना की गई थी। विभिन्न धर्मों में परमात्मा को इसी आकार रूप में मान्यता दी गई। तभी तो विश्व में न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग परमात्मा के स्मृति स्वरूप में प्रसिद्ध हैं बल्कि हर शिवालियों में शिवलिंग प्रतिष्ठित होकर परमात्मा का भावपूर्ण स्मरण करा रहे हैं। वही ज्योतिरूप में धार्मिक स्थलों पर ज्योति अर्थात् दीपक प्रज्ज्वलित कर परमात्मा के ज्योति स्वरूप की साधना की जाती है।

शिव परमात्मा ऐसी परम शक्ति है, जिनसे देवताओं ने भी शक्ति प्राप्त की है। भारत के साथ-साथ मिश्र, यूनान, थाईलैण्ड, जापान, अमेरिका, जर्मनी, जैसे दुनियाभर के अनेक देशों ने परमात्मा शिव के अस्तित्व को स्वीकारा है। धार्मिक चित्रों में स्वयं श्रीराम, श्रीकृष्ण और शंकर भी भगवान शिव की आराधना में ध्यान मग्न दिखाये गए हैं। जैसा कि पुराणों और धार्मिक ग्रन्थों में भी उल्लेख मिलता है। श्री राम ने जहां रामेश्वरम में शिव की पूजा की तो श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध से पूर्व शिव स्तुति की थी। इसी तरह शंकर को भी भगवान शिव में ध्यान लगाते देखे जाने के चित्र प्रदर्शित किये गए हैं। दरअसल शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं शिव परमपिता परमात्मा है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानि शंकर उनके देव तभी तो भगवान शिव को देवों का देव महादेव अर्थात् परमपिता परमात्मा स्वीकारा गया है।

ज्योति बिन्दू रूपी शिव ही अल्लाह अर्थात् नूर ए इलाही है। वही लाईट आफ गोड है

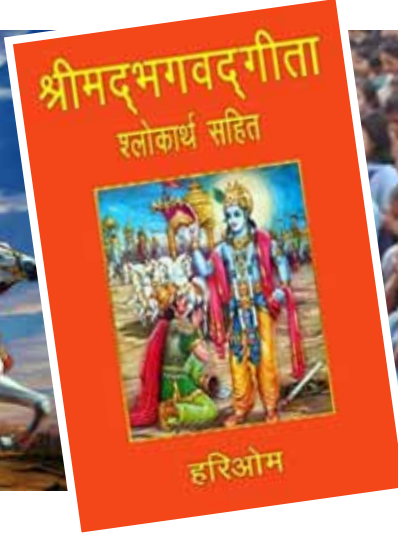
और वही सतनाम है। यानि नाम अलग-अलग परन्तु पूरी कायनात का मालिक एक ही परम शक्ति है जो शिव है।

सिर्फ भारत के धार्मिक ग्रन्थों और पुराणों में ही शिव के रूप में परमात्मा का उल्लेख नहीं है बल्कि दुनियाभर के लोग और यहूदी, ईसाई, मुस्लमान भी अपने अपने अंदाज में परमात्मा को ओम, अल्लाह, ओमेन के रूप में स्वीकारते हैं। सृष्टि की रचना की प्रक्रिया का चिंतन करे तो कहा जाता है कि सृष्टि के आरम्भ में ईश्वर की आत्मा पानी पर डोलती थी और आदिकाल में परमात्मा ने ही आदम व हव्वा को बनाया जिनके द्वारा स्वर्ग की रचना की गई। चाहे शिव पुराण हो या मनुस्मृति या फिर अन्य धार्मिक ग्रन्थ हर एक में परमात्मा के वजूद को तेजस्वी रूप माना गया है। जिज्ञासा होती है कि अगर परमात्मा है तो वह कहाँ है, क्या किसी ने परमात्मा से साक्षात् किया है या फिर किसी को परमात्मा की कोई अनुभूति अनुभूति हुई है। साथ ही यह भी सवाल उठता है कि आत्माये शरीर धारण करने से पहले कहा रहती है और शरीर छोड़ने पर कहा चली जाती है। इन सवालों का जवाब भी सहज ही उपलब्ध है। सृष्टि चक्र में तीन लोक होते हैं पहला स्थूल वतन, दूसरा सूक्ष्म वतन और तीसरा मूल वतन अर्थात् परमधाम। स्थूल वतन जिसमें हम निवास करते हैं पांच तत्वों से मिलकर बना है। जिसमें आकाश पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल शामिल हैं। इसी स्थूल वतन को कर्म क्षेत्र भी कहा गया है। जहां जीवन मरण है और अपने-अपने कर्म के अनुसार जीव फल भोगता है। इसके बाद सूक्ष्म वतन सूर्य, चांद और तारों के पार है जिसे ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी भी कहा जाता है। सूक्ष्म वतन के बाद मूल वतन है जिसे परमधाम कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां परमात्मा निवास करते हैं। यही वह धाम है जहां सर्व आत्माओ का मूल धाम है। यानि आत्माओं का आवागमन इसी धाम से स्थूल लोक के लिए होता है।

आत्माओं का जन्म होता है और परमात्मा का अवतरण होता है। यही आत्मा और परमात्मा में मुख्य अन्तर है। सबसे बड़ा अन्तर यह भी है कि आत्मा देह धारण करती है जबकि परमात्मा देह से परे है। परमात्मा निराकार है और परमात्मा ज्योति बिन्दू रूप में सम्पूर्ण आत्माओं को प्रकाशमान करता है यानि उन्हें पतित से पावन बनाता है।

(लेखक आध्यात्मिक चिंतक व वरिष्ठ साहित्यकार हैं)

देवभूमि के सरकारी स्कूलों में अब 'शिक्षा के साथ संस्कार' भी



उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों का दैनिक पाठ अनिवार्य कर दिया है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ का पाठ नहीं, बल्कि बच्चों के मन, मस्तिष्क और आत्मा को छूने वाली एक सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत है। जहां हर सुबह प्रार्थना सभा गीता के ज्ञान से गुंजेगी और छात्रों को जीवन, मूल्य और आत्मनियंत्रण का बोध कराया जाएगा। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के बाद नियम प्रदेश भर के लगभग 17 हजार सरकारी स्कूलों पर लागू हो गया। शिक्षा निदेशक डॉ. सती ने बताया कि हर दिन स्कूल में गीता के श्लोकों का केवल उच्चारण नहीं होगा, बल्कि उनका अर्थ भी समझाया जाएगा। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सदियों पुरानी जड़ों को फिर से सींचने की एक भावपूर्ण पहल करते हुए 15 जुलाई को उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों का दैनिक पाठ अनिवार्य कर दिया है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ का पाठ नहीं, बल्कि बच्चों के मन, मस्तिष्क और आत्मा को छूने वाली एक सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत है। जहां हर सुबह प्रार्थना सभा गीता के ज्ञान से गुंजेगी और छात्रों को जीवन, मूल्य और आत्मनियंत्रण का बोध कराया जाएगा। इस फैसले के पीछे केवल परंपरा नहीं, बल्कि वह दृष्टिकोण है जो गीता को मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और नैतिक दर्शन का जीता-जागता उदाहरण मानता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों से मेल खाती यह पहल बच्चों को आधुनिक ज्ञान के साथ-साथ भारतीय आत्मा की गहराई से भी जोड़ने की कोशिश है। उत्तराखंड माध्यमिक

शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के बाद मंगलवार से ही नियम प्रदेश भर के लगभग 17 हजार सरकारी स्कूलों पर लागू हो गया है। शिक्षा निदेशक डॉ. सती ने बताया कि हर दिन स्कूल में गीता के श्लोकों का केवल उच्चारण नहीं होगा, बल्कि उनका अर्थ भी समझाया जाएगा। इसका मकसद स्कूली बच्चों को प्राचीन भारतीय परंपराओं से अवगत कराना है। इससे बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने के साथ बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। जारी आदेश में लिखा गया है कि हर दिन एक मूल्य आधारित श्लोक प्रार्थना सभा में बोला जाएगा और सूचना पट पर अर्थ सहित लिखा भी जाएगा। टीचर्स भी समय-समय पर श्लोकों की व्याख्या करते हुए बच्चों को सैद्धांतिक जानकारी देंगे। छात्रों को यह भी बताया जाएगा कि गीता के उपदेश मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, व्यवहार

विज्ञान और नैतिक दर्शन पर आधारित हैं, जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से संपूर्ण मानवता के लिए उपयोगी हैं। आदेश में कहा गया है कि स्कूली स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों को ये श्लोक सिर्फ विषय या रीडिंग मैटेरियल के रूप में नहीं पढ़ाए जाएं बल्कि ये उनके जीवन और व्यवहार में भी वो बातें दिखनी चाहिए। सरकार की इस पहल का उद्देश्य बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली से भी जोड़ना है। सरकारी स्कूलों में गीता का श्लोक पढ़वाने का फैसला सिर्फ एक धार्मिक पहल नहीं, बल्कि छात्रों के भीतर सोचने-समझने की क्षमता को जगाने की कोशिश है। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि हर दिन सिर्फ श्लोक का उच्चारण नहीं होगा, बल्कि उसका अर्थ भी बताया जाएगा, ताकि बच्चों को आत्ममंथन, निर्णय क्षमता और व्यवहारिक जीवन के सिद्धांत समझ में आए। टीचर्स की भूमिका भी सिर्फ

विद्यालयों में बच्चों को गीता के श्लोक पढ़ाने को लेकर उत्पन्न विवाद से मैं, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा के रूप में, अत्यंत चिंतित हूँ: डॉ. गीता खन्ना



उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉ. गीता खन्ना ने कहा कि गीता के श्लोक केवल धार्मिक वाचन नहीं हैं, बल्कि वे जीवन-दर्शन हैं। यह जीवन कौशल (Life Skills) सिखाने का एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है, जो बच्चों में आत्मविवेक, आत्मनियंत्रण और नैतिक मूल्यों का विकास करता है। इसे किसी एक धर्म से जोड़ना या इसका विरोध करना उचित नहीं है।

आज भी हम उस Macule शिक्षा सोच के प्रभाव में हैं, जिसने हमारी संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था को खंडित कर हमें हमारी जड़ों से काट दिया। उसी सोच के तहत हमारे गुरुकुलों को समाप्त किया गया, हमारी भाषाओं, परंपराओं और जीवनशैली को हीन बताया गया, और एक ऐसी शिक्षा प्रणाली थोपी गई जो हमें हमारे मूल्यों और आत्मगौरव से दूर ले गई। इसका परिणाम यह है कि आज हमारे बच्चे डिप्रेशन, एंजायटी, नशे की लूट और साइबर अपराधा जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। और जब हम एक बार फिर अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़कर गीता के श्लोकों के माध्यम से बच्चों को एक सही जीवन-दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं।

डॉ. गीता खन्ना ने कहा कि भारत एक धार्मिकराष्ट्र है, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। लेकिन धार्मिकनिरपेक्षता का यह अर्थ नहीं कि हम किसी ऐसे ज्ञान को, जो बच्चों के मानसिक, नैतिक और व्यवहारिक विकास में सहायक हो, केवल धार्मिक कहकर खारिज कर दें।

डॉ. गीता खन्ना ने कहा कि यूरोप, अमेरिका और अन्य कई देश गीता को स्कूलों के जीवन कौशल और मानसिक स्वास्थ्य के पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।

डॉ. गीता खन्ना ने कहा कि मैं सभी नागरिकों, शिक्षाविदों से आग्रह करती हूँ कि वे इस विषय को धर्म के दृष्टिकोण से न देखकर, बच्चों के समग्र विकास और कल्याण के दृष्टिकोण से देखें। यदि कोई भी ग्रंथ, किसी भी धर्म का, बच्चों को जीवन में सही मार्ग दिखाने में सक्षम है, तो उसका विरोध करना न केवल अनुचित है बल्कि सामाजिक न्याय के विरुद्ध है।

सरकार ने साफ किया है कि गीता को केवल धार्मिक ग्रंथ मानकर न पढ़ाया जाए, बल्कि उसे मनोविज्ञान, व्यवहार विज्ञान और नैतिक दर्शन की दृष्टि से देखा जाए। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उन उद्देश्यों से मेल खाती है, जिनमें पारंपरिक भारतीय ज्ञान को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने पर जोर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2 महीने पहले 20 मई को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। सात मई को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर करके कई आतंकी अड्डों को तहस-नहस कर दिया था। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाने का आदेश जारी किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने राज्य में मदरसा पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर एक पूरा अध्याय शुरू करने का निर्णय लिया। जिसमें भारतीय सेना की वीरता और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणादायक कहानी शामिल होगी। पूरे उत्तराखंड में 451 पंजीकृत मदरसों में 50,000 से अधिक छात्र नामांकित हैं, जो अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने कहा कि उत्तराखंड के मदरसों के पाठ्यक्रम में, हाल में भारतीय सैन्य बलों द्वारा पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' की गाथा को शामिल किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष मुप्ती शमून कासमी ने यहां जारी एक बयान में कहा, "हम मदरसों में सफल ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को शामिल करेंगे ताकि हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को यह मालूम हो सके कि यह ऑपरेशन क्या था और इसकी जरूरत क्यों पड़ी।" पाकिस्तान को 'नापाक मुल्क' बताते हुए कासमी ने कहा कि जिस तरह से उसने हमारे देश पर हमला किया और पहलगाम में 'हमारे निहत्थे भाइयों' का कत्ल किया, उसके लिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। उन्होंने इस कृत्य को कुरान की भी अवहेलना बताया। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्णय पर अमल के लिए जल्दी ही पाठ्यक्रम समिति की बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में लगातार मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है।

पाठ पढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी। वे प्रश्नों के जरिए बच्चों की सोच को दिशा देने और नैतिकता के पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि इससे गीता छात्रों के लिए किताब नहीं, बल्कि व्यवहार में उतरने वाला ज्ञान बन सकेगी और यही है इस फैसले की असली क्रांतिकारी सोच है।

श्रीमद्भागवत गीता के श्लोक से विद्यार्थियों के चरित्र, निर्माण और नैतिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी

माना जा रहा है कि इससे छात्रों के चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों, आत्मनियंत्रण, निर्णय क्षमता और वैज्ञानिक सोच को मजबूती मिलेगी। धामी सरकार के इस निर्णय का समर्थन मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुप्ती शमून कासमी ने भी किया है। उन्होंने कहा, राम और कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, और हर भारतीय को उनके बारे में जानना चाहिए। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाने के लिए संस्कृत विभाग के साथ एमओयू की योजना बनाई जा रही है।

शुद्ध खाद्य उत्पादों का हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव



डाइटिशियन वंदना,
फीमेल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट

आज के युग में जब मिलावट, प्रोसेस्ड फूड्स और कैमिकल्स से भरे आहार हमारे चारों ओर फैले हुए हैं, ऐसे समय में शुद्ध खाद्य उत्पादों (Pure and

Unadulterated Foods) का सेवन हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। शुद्ध आहार न केवल हमें रोगों से बचाता है बल्कि जीवन उर्जा, पाचन, त्वचा, हार्मोन्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक संतुलन को भी सुदृढ़ करता है।

क्या होते हैं शुद्ध खाद्य उत्पाद?

शुद्ध खाद्य उत्पाद वे होते हैं जो बिना रासायनिक मिलावट, कृत्रिम रंग, प्रिज़र्वेटिव, कीटनाशक या सिंथेटिक एडिटिव्स के प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हो जैसे जैविक फल-सब्जियाँ (Organic Fruits & Vegetables), देशी घी, शुद्ध दूध, साबुत अनाज, देशी दालें, बिना कैमिकल मिला, बनाये गये मसाले, शहद, गुड़, खांड, नमक इत्यादि। संस्कृत में कहा गया है- “शुद्ध भोजनं शुद्ध मनः” अर्थात् शुद्ध भोजन से मन भी शुद्ध होता है।

शुद्ध खाद्य उत्पादों का शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव।

1-रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि- शुद्ध खाद्य उत्पादों में एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन्स

और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं जिससे शरीर की इम्युनिटी मजबूत होती है उदाहरणः जैविक हल्दी में करक्यूमिन ज्यादा होता है जो सूजन और संक्रमण से बचाव करता है।

2-पाचन तंत्र में सुधार- कैमिकल मुक्त आहार हमारे पाचन एंजाइम्स को उत्तेजित करता है जिससे गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याएं कम होती हैं।

3-हार्मोन संतुलन- प्रोसेस्ड फूड्स में पाए जाने वाले जेनोएस्ट्रोजेन्स (xenoestrogens) हमारे हार्मोन को प्रभावित करते हैं। शुद्ध आहार शरीर को डिटॉक्स करता है और थायरॉइड, इनफर्टिलिटी, पीसीओएस जैसी समस्याओं में राहत देता है।

4-त्वचा और बालों की गुणवत्ता में वृद्धि- शुद्ध खाद्य उत्पादों में मौजूद पोषक तत्व जैसे बायोटिन, विटामिन A,C,E त्वचा को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाते हैं।

मानसिक और आत्मिक प्रभाव

1-एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता- रासायनिक भोजन मानसिक धुंध (Brain Fog), तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ाता है जबकि सात्विक शुद्ध भोजन ध्यान, स्मृति और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है।

2-नींद में सुधार- कैफीन, प्रिज़र्वेटिव्स और चीनी से भरे खाद्य उत्पाद नींद पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। शुद्ध आहार मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन को संतुलित करते हैं जिससे नींद अच्छी आती है।

3-सकारात्मक उर्जा और भावनात्मक स्थिरता- भारतीय आयुर्वेद में शुद्ध आहार को सत्वगुणी आहार माना गया है। यह मन में शांति, प्रेम और करुणा जैसे भाव उत्पन्न

करता है।

मिलावटी खाद्य उत्पादों से होने वाले नुकसान:

1-कैंसर, हार्मोनल डिसऑर्डर, डाइबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है।
2-बच्चों की ग्रोथ और मानसिक विकास में रूकावट।

3-फूड एलर्जी, मेटाबोलिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन।

4-लिवर और किडनी पर अतिरिक्त बोझ।

समाधानः कैसे सुनिश्चित करें कि भोजन शुद्ध है?

1-लेबल पढ़ें- Preservative Free, No Artificial Colour, No Artificial Flavor.

2-जैविक उत्पादों को प्राथमिकता दें।

3-भरोसेमंद ब्रांड के उत्पादों की खरीदारी करें।

4-रिफाईंड ऑयल की जगह कोल्ड प्रेस्ड सरसो तेल अपनाएं।

5-घर पर साधारण परीक्षण से शुद्धता की जांच करें।

शुद्ध भोजन केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक जीवनशैली है। यह शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए औषधी समान है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारी आने वाली अगली पीढ़ी रोग मुक्त होकर उर्जा से भरपूर और मानसिक रूप से संतुलित जीवन जीएं तो हमें आज से ही शुद्ध आहार की ओर लौटना ही होगा।

“आपका भोजन ही आपकी दवा बन सकता है-बशर्ते वह शुद्ध और संतुलित हो”

विपक्ष की लोकतंत्र पर चिंता या सत्तालोभ की राजनीति?



ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र

आज विश्व के सबसे बड़े, जीवंत और जागरूक लोकतंत्रों में गिना जाता है। यह संविधान

न की मजबूत

नींव, संस्थाओं की पारदर्शिता और जनता की जागरूकता से संचालित होता है। परंतु विडंबना यह है कि देश का विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी, बार-बार लोकतंत्र और संविधान पर खतरे की झूठी दुहाई देकर एक अनावश्यक और निरर्थक बहस छेड़ते रहे हैं, वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा को घेरने एवं दोषी ठहराने के लिये न केवल उन पर आधारहीन आरोप लगाते रहते हैं, वरन देश की संवैधानिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और संविधान के ही खतरे में होने का राग अलापते हुए उन्हें लांछित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे नेता संविधान की दुहाई देते हैं, वे स्वयं संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। लोकतंत्र की आत्मा पर इस तरह का प्रहार विपक्ष की भूमिका पर एक बड़ा प्रश्न है। विडम्बना एवं चिन्ताजनक है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं में भी मोदी-भाजपा का विरोध करते-करते देश-विरोध पर उतर जाते हैं, जिससे विदेशों में भारत की छवि का भारी नुकसान होता है और विदेशियों को

लगता था कि भारत में लोकतंत्र और संविधान ढह रहा है।

नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं उनके सहयोगी जब यह कहते हैं कि 'देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है', 'संविधान खतरे में है', तब यह केवल एक राजनीतिक शगूफा प्रतीत होता है, न कि कोई तर्कसम्मत आलोचना। यदि वास्तव में लोकतंत्र खतरे में होता, तो क्या वे हर मंच से खुलकर सरकार की आलोचना कर पाते? क्या संसद, मीडिया, चुनाव आयोग, और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं उनके वक्तव्यों को स्थान देती? असल में तो 1975 में लोकतंत्र एवं संविधान खतरे में आये थे जब तत्कालिन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने हेतु अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 'आंतरिक अशांति' के आधार पर आपातकाल लगाया तथा लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर हजारों नेताओं एवं बेगुनाह लोगों को कठोर कानूनों के अंतर्गत जेल भेज दिया। आजादी के बाद तब पहली और आखरी बार लोकतंत्र खतरे में आया था, तब संविधान भी खतरे में चला गया था। राहुल गांधी अपने गिरेबान में झांकने एवं कांग्रेस के अतीत को देखने की बजाय मोदी-भाजपा पर लोकतंत्र एवं संविधान को खतरे में डालने का बेबुनियाद, भ्रामक एवं आधारहीन आरोप मढ़ते हैं। इन त्रासद स्थितियों में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा नहीं, बल्कि अपने खोए हुए जनाधार को पुनः प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। विशेषतः

लोकसभा हो या विधानसभा के चुनाव-इनमें जरूरी एवं जनता से जुड़े विषयों को उठाने की बजाय लोकतंत्र एवं संविधान के खतरे में होने के राग से जनता को गुमराह करना आम बात हो गयी है।

देशभर में एवं अनेक राज्यों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार आदि के अवैध घुसपैठियों बड़ी मात्रा में घुस आये हैं। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिये इन घुसपैठियों को इन विपक्षी दलों की शह पर ही जगह मिल रही है, ये घुसपैठियें न केवल फर्जी तरीकों से आधार, पैन, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेज प्राप्त कर कई निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता-सूचियों में अपना नाम अंकित करा लिया है। यह लोकतंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनसंख्या संतुलन के लिए गंभीर खतरा है, चुनाव आयोग ने इस पर अपना रुख सख्त करते हुए सभी राज्यों में 'मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण' का निर्णय लिया है। बिहार में वह ऐसे लोगों की पहचान संबंधी पहल कर चुका है, पर विपक्ष को इस पर आपत्ति है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी। न्यायालय ने आयोग की इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई।

विपक्ष लम्बे समय से चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है, कभी निष्पक्ष मतदान पर तो कभी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर सवाल उठाते रहा है। चूंकि चुनाव ही सत्ता की सीढ़ी है, इसलिए लोकसभा चुनाव में परास्त होने और अनेक राज्यों में अप्रासंगिक होने से चुनाव आयोग पर आरोप तथा लांछन

लगाना विपक्ष के लिए कभी आसान हो गया है। कभी वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों और निर्णयों पर अंगुली उठाता है, कभी उसे भाजपा के इशारे पर काम करने वाला बताता है, कभी ईवीएम, मतदाता सूची में अनियमितता, डाटा देने में विलंब, दलीय पक्षपात आदि का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग की छवि नष्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को हरी झंडी देकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी। विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना और वैकल्पिक नीतियों के माध्यम से शासन को दिशा देना होती है। किंतु आज का विपक्ष न तो पाकिस्तान-चीन के खतरनाक मनसुबों, न गरीबी, न महंगाई, न बेरोजगारी, न सांप्रदायिक सौहार्द, न सीमा पर पड़ोसी देशों की चुनौती, और न ही किसानों, युवाओं और महिलाओं की समस्याओं को लेकर कोई ठोस योजना प्रस्तुत कर पा रहा है और न ही इन बुनियादी मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा पा रहा है। उनकी राजनीति केवल मोदी और भाजपा विरोध तक सीमित होकर रह गई है। जब राजनीति 'विकास' की बजाय 'विरोध' पर केंद्रित हो जाए, तो वह जनहित नहीं, केवल सत्ता की भूख बन जाती है। विपक्षी दल मोदी एवं भाजपा पर लगातार आक्रामक हैं। राहुल गांधी और अन्य दलों के नेता संविधान की प्रति लहराकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे संविधान खतरे में है और उन्हें उसे बचाना है। लेकिन भारत की जनता अब परिपक्व एवं समझदार हो गयी है, उसे अच्छा-बुरे में फर्क दिखता है। भाजपा पर 'तानाशाही', 'संविधान बदलने की साजिश', 'जनविरोधी नीतियों' जैसे आरोप लगाना विपक्ष की आदत बन चुकी है। किंतु हर बार जनता ने चुनाव में स्पष्ट बहुमत देकर इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जनता जानती है कि ऑपरेशन सिन्दूर, डिजिटल इंडिया, गरीबमुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, महिला आरक्षण, जी-20 की सफल अध्यक्षता, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, उन्नत सड़कें, चमकती रेल एवं चमकते रेलवे स्टेशन, घर, शौचालय और जल जैसी योजनाएं सिर्फ नारों से नहीं, संकल्प और समर्पण से संभव हुई हैं।

क्या राहुल गांधी या इंडी गठबंधन के पास कोई ठोस आर्थिक नीति, सुरक्षा रणनीति, या सामाजिक समरसता का ब्लूप्रिंट है? क्या वे यह बता सकते हैं कि वे भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, या केवल मोदी विरोध को ही नीति मान बैठे हैं? भारतीय जनता राजनीतिक रूप से परिपक्व हो चुकी है। वह अब भावनात्मक और भ्रामक नारों के बजाय ठोस उपलब्धियों और दूरदर्शिता को प्राथमिकता देती है। ऐसे में विपक्ष का यह दुष्प्रचार केवल उनकी साख को ही नुकसान पहुंचा रहा है। विपक्ष को चाहिए कि वह सकारात्मक राजनीति करे, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत करे, और जनता के विश्वास को अर्जित करे, न कि लोकतंत्र के अस्तित्व को ही संदेह के घेरे में लाकर अपनी किलताओं पर पर्दा डाले। राजनीति केवल विरोध नहीं, समाधान का माध्यम होनी चाहिए।

डॉ आर मीनाक्षी सुंदरम इंटरनेशनल गुडविल सोसायटी ऑफ इंडिया की परमानेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य मनोनीत हुए



शिक्षाविदों एवं ब्यूरोक्रेट्स की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल गुडविल सोसायटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत के पूर्व रक्षा सचिव डॉ. योगेंद्र नारायण, आईएएस (रि.) ने उत्तराखंड शासन के प्रमुख सचिव डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम, आईएएस को IGSI की सर्वोच्च पॉलिसी मेकिंग बॉडी परमानेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल

का सदस्य नामित किया। परमानेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य आजीवन होता है और इसे किसी भी रीति से हटाया नहीं जा सकता है।

विदित हो कि जिन उद्देश्यों को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉ. नागेंद्र सिंह ने IGSI की स्थापना की थी, आज उन्हीं मुद्दों को लेकर दुनिया भर के वैश्विक नेता चिंतित हैं।

डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम वर्तमान में इंटरनेशनल गुडविल सोसायटी ऑफ इंडिया के देहरादून उत्तराखंड चैप्टर के अध्यक्ष हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अन्य सदस्यों में उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव श्री सुभाष कुमार भी शामिल हैं।



महाराज ने केन्द्रीय मंत्री से ऐतिहासिक स्थलों पर शोध का किया अनुरोध

सिन्धु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट का किया जाए अनुवाद



हमारे देश में अनेकों ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिन पर शोध किया जाना आवश्यक है। इतना ही नहीं इन स्थानों पर अंकित लिपि का हमारी सभ्यता एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से अनुवाद किया जाना भी बेहद जरूरी है।

उक्त बात प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, लोकनिर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम, मंत्री सतपाल महाराज ने केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को लिखे एक पत्र के माध्यम से कही है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री श्री शेखावत से कहा है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता के स्क्रिप्ट का अनुवाद करवाया जाना चाहिए। उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा में स्थित पाषाणकालीन लखुडियार की अति प्राचीन पेंटिंग का इतिहास, जौनसार क्षेत्र में स्थित प्राचीन गुफाओं एवं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के रहस्य आदि पर भी पुरातत्व विभाग के माध्यम से शोध किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

संस्कृति मंत्री श्री महाराज ने कहा कि हमारी समृद्ध संस्कृति और यहाँ के 'प्राचीन इतिहास एवं सभ्यता पर गहन शोध की

आवश्यकता है। हमारे देश में अनेकों ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिन पर अंकित लिपि का अनुवाद और शोध होना जरूरी है। उन्होंने केन्द्रीय संस्कृति मंत्री से अनुरोध किया है कि सिन्धु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट का अनुवाद करवाने के साथ-साथ बलूचिस्तान के लोगों द्वारा जो ब्राह्मी भाषा का प्रयोग किया जाता है वह हमारी तमिल, तेलगू और मलयालम से मिलती-जुलती है। कन्धार में बसे लोग गन्धारी की संतान बतायी जाती है ये सभी हमारी संस्कृति का अनुसरण करते हैं अतः इन सभी पर शोध किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

प्रदेश के संस्कृति मंत्री श्री महाराज ने केन्द्रीय मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि उत्तराखण्ड के अल्मोड़ा में स्थित पाषाण कालीन लखुडियार की अति प्राचीन पेंटिंग का इतिहास, जौनसार क्षेत्र में स्थित प्राचीन गुफाओं एवं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के रहस्य आदि पर भी पुरातत्व विभाग के माध्यम से शोध किया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे हमारी नई पीढ़ी को हमारी समृद्धशाली संस्कृति एवं इतिहास की विस्तृत जानकारी मिल सके और इससे वह लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का विदेशों में भी अप्रत्यक्ष रूप से अनुसरण किया जाता है। इराक के कुर्द लोग अपने घर में मोर की फोटो लगाते हैं, यूरोप में बसे हुए उत्तर भारत मूल के जिप्सी समाज के लोग हस्तरेखा देखकर भविष्य बताने का काम करते हैं।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री श्री शेखावत से अनुरोध किया कि ऐतिहासिक स्थलों एवं विदेशों में हमारी संस्कृति को धारित किये विभिन्न जाति के लोगों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कराते हुए इसमें शोध करवाये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाये।

मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में हिंदी फिल्म '5 सितम्बर' का पोस्टर लॉन्च



मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में हिंदी फिल्म '5 सितम्बर' का पोस्टर लॉन्च किया। यह फिल्म पूर्णतः उत्तराखंड में फिल्माई गई है तथा राज्य की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय प्रतिभा को राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शित करने का सशक्त प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड फिल्म निर्माण का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फिल्म नीति के तहत हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है, ताकि अधिक से अधिक निर्माता-निर्देशक उत्तराखंड की धरती पर फिल्म निर्माण करें और राज्य के युवाओं को रोजगार और मंच प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की फिल्में न केवल उत्तराखंड की प्रतिभा को प्रोत्साहित करती हैं, बल्कि पर्यटन एवं सांस्कृतिक संवर्धन में भी सहायक सिद्ध होती हैं। उन्होंने फिल्म निर्माण टीम को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि यह फिल्म दर्शकों के मन को छूने में सफल होगी।

इस अवसर पर फिल्म के डायरेक्टर श्री कुनाल शमशेर मल्ला, कलाकार श्री संजय मिश्रा, श्री ब्रिजेंद्र काला, श्री ऋषभ खन्ना, श्री भुवन खन्ना और श्री दीपराज राणा मौजूद थे।

जनभागीदारी से ही टीबी उन्मूलन संभव- राज्यपाल

राज्यपाल ने टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को किया सम्मानित



राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने मंगलवार को राजभवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित “टीबी मुक्त भारत अभियान” के अंतर्गत पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने टीबी रोगियों को गोद लेकर नियमित निगरानी और मानसिक संबल प्रदान कर रोगियों के स्वस्थ होने में मदद करने वाले 13 निःक्षय मित्रों को सम्मानित किया। वहीं उन्होंने 13 ट्रीटमेंट सपोर्टर्स को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य कर, रोगियों के उपचार की नियमित मॉनिटरिंग और उनकी समुचित देखभाल की। (सूची संलग्न) इस दौरान राज्यपाल ने टीबी उन्मूलन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपदों देहरादून, चम्पावत और रुद्रप्रयाग को भी सम्मानित किया। उन्होंने टीबी रोग से स्वस्थ हुए ‘टीबी चौपियनों’ को भी सम्मानित किया और गोद लिए गए टीबी मरीजों को पोषण किट प्रदान की।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि टीबी उन्मूलन केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए जनभागीदारी और सामूहिक संकल्प आवश्यक है। उन्होंने कहा कि टीबी से स्वस्थ हुए लोग असली योद्धा हैं और समाज के लिए प्रेरण बन सकते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी लोगों, स्वयं सेवी संस्थाओं और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की और कहा

कि इन सभी लोगों की मेहनत से हमारा प्रदेश अग्रणी राज्यों में है।

राज्यपाल ने बताया कि उन्हें भी निःक्षय मित्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और अब तक उन्होंने 75 टीबी रोगियों को गोद लिया है, जिनमें से 62 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने समाज के सामर्थ्यवान व्यक्तियों से अपील की कि वे भी आगे आकर निःक्षय मित्र बनें और इस अभियान को गति दें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से आग्रह किया कि जानकारी के अभाव में कोई भी रोगी उपचार से वंचित न रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि अभियान अंतिम छोर तक पहुंचे और प्रत्येक रोगी को समुचित देखभाल एवं उपचार मिल सके। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से प्रदेश को 2025 में टीबी मुक्त बनाने में सफल होंगे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखण्ड को पूरी तरह से टीबी मुक्त बनाना और इस राष्ट्रीय प्रयास में अग्रणी भूमिका निभाना है। हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त अभियान को 01 अगस्त, 2025 से राज्य भर में एक व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत सभी नगर पंचायतों के वार्डों और नगर निगमों के सभी पार्षद वार्डों में विशेष शिविर (कैंप) लगाए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य समुदाय स्तर पर टीबी के मामलों की पहचान

करना, उनका उपचार सुनिश्चित करना और जागरूकता फैलाना होगा।

इस कार्यक्रम में सचिव श्री राज्यपाल श्री रविनाथ रामन, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, अपर सचिव श्री राज्यपाल श्रीमती रीना जोशी, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. सुनीता टम्टा, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना, चेयरमैन रेडक्रॉस सोसायटी डॉ. नरेश चौधरी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी व मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

सम्मानित होने वाले लोगों की सूची-

सम्मानित होने वाले निःक्षय मित्र में हिमालयन वेलनेस कम्पनी के डॉ. फारुख, हंस कल्चरल फाउंडेशन की सुश्री पूनम किमोटी, देहरादून के श्री मुकेश मोहन, श्री पंकज गुप्ता, साईं इंस्टीट्यूट की डॉ. आरती, रेडक्रॉस सोसायटी की सुश्री कल्पना बिष्ट, कनिष्क हॉस्पिटल की डॉ. रितु गुप्ता, आस संस्था की सुश्री हेमलता बहन, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के श्री राजीव बिजल्वाण, देव भूमि स्वराज फाउंडेशन के श्री इन्दर रमोला, महिला जिजीविषा मंच देहरादून की सुश्री डॉली डबराल, लायंस क्लब के श्री रजनीश गोयल और सुश्री ममता थापा शामिल हैं।

वहीं ट्रीटमेंट सपोर्टर्स में कम्युनिटी वॉलंटियर सुप्रिया, जोया, कनक एवं आशा कार्यकर्त्रियों में नीरज, नीरा कंडारी, मीना काला, गंगा भंडारी, सरोज, नीरू जैन, पूजा जोशी, शिखा अरोड़ा, निर्मला जोशी एवं सचि तिवारी को सम्मानित किया गया।

अपने काम और व्यवहार से उत्तराखण्डियों की विशेष पहचान- दुष्यंत गौतम!



जन्मभूमि और मातृभूमि के साथ उत्तराखंड देवभूमि देश को प्रेरणा देने का कार्य करती है। चाहे उत्तरायणी हो या हरेला प्रकृति के सम्मान और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दुनियाभर को उत्तराखंड से ही मिलता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि के प्रति विशेष प्रेम भाव है और यहां की मातृशक्ति और समर्पित मेहनती लोगों के बल पर ही इस दशक को उत्तराखंड का दशक कहा जाता है।

ये विचार नई दिल्ली के गोल मार्केट स्थित जैन भवन में पर्वतीय लोकविकास समिति और अपनी धरोहर न्यास द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हरेला उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम ने व्यक्त किए।

हरेला उत्सव का उद्घाटन करते हुए नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा कि हरेला अब उत्तराखंड से आगे निकलकर पूरे देश का राष्ट्रीय उत्सव बन रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान 'एक वृक्ष माँ के नाम' में हरेला की ही प्रेरणा है। जन-जन को हरियाली को बढ़ाने और वृक्षारोपण को दिनचर्या का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। यह खुशी की बात है कि पर्वतीय लोकविकास समिति की पहल हरेला को केवल पेड़ लगाने मात्र तक सीमित न कर उसे धरोहर मानकर उसकी रक्षा और पोषण की जिम्मेदारी लेने का अभियान है। निश्चित रूप से हरेला लोगों में जागृति लाने का काम करेगा।

पर्वतीय लोकविकास समिति के परामर्शदाता और उत्तराखंड भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ

के संयोजक और पैनलिस्ट प्रवक्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री राजेश्वर पैन्थली ने स्वागत वक्तव्य देते हुए कहा कि दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के स्वाभिमान और पहचान, अपनी लोकसंस्कृति, धार्मिक महत्ता और बोली भाषा के संरक्षण के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। पहाड़ की बौद्धिक प्रतिभाओं, अपने जनप्रतिनिधियों और सामान्य जनों को एक मंच पर लाकर हम देवभूमि के गौरव को बढ़ाने के साथ उसके विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। समारोह के विशिष्ट अतिथि पटपडुंगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रविंद्र सिंह नेगी ने कहा कि दिल्ली में पहाड़ के लोग अपनी योग्यता, कर्मठता और ईमानदारी के लिए तो जाने ही जाते हैं लेकिन हमारे उत्सव और संस्कृतिक कार्यक्रम भी समाज में बड़ा और व्यापक संदेश देते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तरायणी अभियान दिल्ली में 20 वर्ष में राष्ट्रीय अभियान सिद्ध हुआ है इसी प्रकार पर्वतीय लोकविकास समिति की पहल पर एक व्यापक स्वरूप में हरेला पर्व भी लोकप्रिय सिद्ध होगा। इस अवसर पर भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी डॉ. (आई.आर. एस.) डी.पी. सेमवाल (पूर्व प्रधान आयकर आयुक्त पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद सिंह रावत, सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, प्रशासक और संसदीय संस्कृत परिषद के अध्यक्ष डॉ. जीतराम भट्ट, उत्तराखंड से आए विख्यात कृषि विज्ञानी श्री नरेंद्र मेहता, शीर्ष शिक्षाविद और लेखक प्रो. सुरेश बंदूनी, वरिष्ठ साहित्यकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक प्रो. हरेंद्र सिंह असवाल, शिक्षाविद श्री संजय भारतीय, पूर्व

निगम पार्षद और भाजपा नेत्री श्रीमती माया सिंह बिष्ट, लेखक और भाषाविद श्री रमेश चंद्र घिल्डियाल, पूर्व शिक्षा उपनिदेशक और समाजसेवी डॉ. राजेश्वरी कापड़ी, शिक्षाविद एवं समाजसेवी श्री लाखीराम डबराल और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एवं समाजसेवी श्री दुर्गा सिंह भंडारी को राष्ट्र गौरव सम्मान प्रदान किया गया। धरोहर सम्मान से सामाजिक कार्यकर्ता श्री नेपाल सिंह, शिक्षाविद और लेखक डॉ. मनोज कुमार कौन, पत्रकार और समाजसेवी श्री मंगल सिंह नेगी, श्री अनिल पंत, सामाजिक कार्यकर्ता शशि मोहन रावत, श्रीमती लक्ष्मी नेगी, श्रीमती तृप्ति जोशी, समाजसेवी श्री राजेश डंडरियाल, श्री दिनेश बम, श्री संजय मठपाल, डॉ. नवदीप जोशी और डॉ. विपिन मैखुरी को सम्मानित किया गया।

दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों से आई पहाड़ समाज की बहनों ने भक्ति भाव से युक्त भजन और हरेला गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किए। ढोल दमाऊं, मशकबीन और रणसिंगा पर युवाओं के साथ उपस्थित लोग भी झूम उठे।

अपनी धरोहर के अध्यक्ष श्री विजय भट्ट ने हरेला की अवधारणा और आगे की कार्ययोजना पर वृत्त रखा। पर्वतीय लोकविकास समिति के चेयरमैन डॉ. शशि मोहन शर्मा और संयोजक कुंदन सिंह रौथान ने सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया।

पर्वतीय लोकविकास समिति के अध्यक्ष और अपनी धरोहर दिल्ली के संयोजक प्रो. सूर्य प्रकाश सेमवाल ने कहा कि उत्तरायणी अभियान की तरह हमारा हरेला पर्व का जनजागरण भी सिद्धि की ओर बढ़ेगा। क्योंकि अब प्रत्येक देशवासी पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जल के संकट के विषय में जन रहा है। हम भी यही चेतना जागृत करेंगे कि हरेला में पेड़ केवल पहाड़ वालों को नहीं, बल्कि सबको लगाने होंगे और जो लगाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा, देखभाल और उचित पोषण की चिंता करनी होगी। कार्यक्रम के अंत में हिम उत्तरायणी पत्रिका के प्रबंधक श्री विजय सती ने सबका आभार व्यक्त किया।



उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान (आई0आर0डी0टी0),
देहरादून, उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड के राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश लेकर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करें।

क्या आप अपने जूनून को कैरियर में बदलने के लिये तैयार हैं ? उत्तराखण्ड के राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में हम उन अत्याधुनिक क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिनकी अतिरिक्त माँग है।

राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान में प्रवेश क्यों ?

➤ उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित तीन वर्षीय पॉलीटेक्निक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् की कक्षा-12 (इण्टरमीडिएट) उत्तीर्ण की समकक्षता प्राप्त है।

➤ व्यवहारिक शिक्षा- अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं के साथ व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करें। उद्योग केन्द्रित पाठ्यक्रम यह सुनिश्चित करता है कि आप पहले दिन से ही नौकरी के लिये तैयार हैं।

➤ विशेषज्ञ संकाय- अनुभवी पेशेवरों एवं उद्योग जगत के विशेषज्ञों से सीखें जो आपकी सफलता के प्रति समर्पित हैं।

➤ विविध कार्यक्रम- चाहें आप इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी अथवा डिजाइन में रुचि रखते हों आपके कैरियर लक्ष्यों के अनुरूप कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

➤ उद्योग सह-सम्बन्ध- इण्टर्नशिप सेवायोजन और नेटवर्किंग अवसरों के लिये अग्रणी उद्योगों के साथ हमारी मजबूत साझेदारी से लाभ उठायें।

➤ आधुनिक सुविधायें- नवीनतम तकनीकी से सुसज्जित अत्याधुनिक कक्षाओं और सुविधाओं में अध्ययन की सुविधा।

➤ सहायक वातावरण- शैक्षणिक सलाह से लेकर कैरियर परामर्श की उपलब्धता।

➤ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभागों में जूनियर इंजीनियर (कनिष्ठ अभियंता) के पदों के लिये डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-गेल, ओ0एन0जी0सी0, डी0आर0डी0ओ0, सेल, टी0एच0डी0सी0, भेल, एन0टी0पी0सी0, बी0एस0एन0एल0 आदि के साथ ही निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित उद्योगों में भी रोजगार के प्रचुर अवसर उपलब्ध है।

➤ पूर्व के वर्षों में राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों से डिप्लोमा उत्तीर्ण 70 प्रतिशत छात्र विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों में 03 से 06 लाख प्रतिवर्ष के वेतन पर सेवायोजित हुये हैं।

➤ डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप/स्वरोजगार हेतु अनुदान में प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

➤ डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्रों हेतु उच्च तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियरिंग स्नातक (बी0ई0/बी0टेक0) पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में सीधे प्रवेश (लेटरल एंट्री) की सुविधा उपलब्ध है।

➤ 10वीं उत्तीर्ण छात्र को डिप्लोमा के साथ-साथ बी0टेक0 06 वर्ष में पूर्ण करने का सुनेहरा अवसर मिलता है।

॥ विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश हेतु सम्बन्धित संस्थानों से तुरंत सम्पर्क करें॥

“एक जीवंत शिक्षण समुदाय का हिस्सा बनने का अवसर ना चूकें जो आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिये सशक्त बनाता है।”

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह



पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धार्मिक अनुष्ठान आदि)



मेघ राशि- आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई संबंधी गतिविधियों पर पूरी तरह ध्यान देंगे। अपनी भावनाओं में बहकर किसी से भी अपने कामों और योजनाओं के बारे में बातचीत ना करें। नौकरी में इस समय अपने टारगेट को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। भाग्यशाली रंग- केसरिया



वृषभ राशि- आप सभी चिंताओं को छोड़कर हल्के-फुल्के मूड में रहेंगे। बच्चों की गलतियों पर उन्हें डांटने से उनके अंदर हीन भावना आ सकती है। सहयोगियों और कर्मचारियों की सलाह आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। विवाहित जीवन में सही तालमेल बनाकर रखें। कामकाज की अधिकता की वजह से मानसिक तनाव रह सकता है। भाग्यशाली रंग- नारंगी



मिथुन राशि- सुख-सुविधा संबंधी कार्यों में अधिक खर्चा होगा। अपनी काम करने की क्षमता को बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि आलस की वजह से कुछ काम रुक सकते हैं। जीवन साथी का पारिवारिक देखभाल व तालमेल बनाकर रखने में पूरा ध्यान रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन बदलते वातावरण से सावधानी बरतें की आवश्यकता है। भाग्यशाली रंग- लाल



कर्क राशि- युवाओं के लिए अपनी योजनाओं को शुरू करने का अच्छा समय है। व्यवसायिक विकास के लिए अपने संपर्कों को और अधिक बढ़ाएं। दूसरों की सलाह पर भी ध्यान दें इससे आपको कुछ जरूरी जानकारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति कुछ ठीक रहेगी खर्चें बढ़ेंगे लेकिन ज्यादा उधार या लोन ना लें। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी। भाग्यशाली रंग- पीला



सिंह राशि- आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई सफलताएं भी बनाएगी। युवाओं को पहली कमाई मिलने से खुशी रहेगी। किसी भी नकारात्मक स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालें। कुछ नई सफलताएं सामने आएंगी। व्यवसाय में कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बन सकती है प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। भाग्यशाली रंग- बादामी



कन्या राशि- कोई अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें नहीं तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। आप अपनी योग्यता व काबिलियत द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और सफल भी होंगे। आपसी संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। अपने व्यवहार को सहज बनाकर रखें। भाग्यशाली रंग- क्रीम



तुला राशि- ग्रह स्थिति आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रही है, रुके हुए कार्यों को पूरा करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दें। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के सही परिणाम मिलेंगे। स्टेशनरी, कपड़े के व्यवसाय फायदे की स्थिति में रहेंगे। प्रेम संबंध मर्यादा पूर्ण रहेंगे। बहुत ज्यादा थकान की वजह से कमजोरी और सिरदर्द रह सकता है। भाग्यशाली रंग - सफेद



वृश्चिक राशि- आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। अगर संपत्ति के बंटवारे संबंधी विवाद चल रहा है तो आपसी बातचीत करके सुलझेंगे। दूसरों पर भरोसा करने की बजाय अपनी चीजों की संभाल खुद करें। कार्यक्षेत्र में अपने सहयोगी तथा स्टाफ का अनुभव व योगदान आपके लिए सहायक साबित होगा। पति-पत्नी के बीच आपसी प्रेम और तालमेल सही बना रहेगा। भाग्यशाली रंग- लाल



धनु राशि- धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में अपनी आस्था और रुझान रखने से आपके व्यक्तित्व और अच्छा होगा। युवा बेकार की मौज मस्ती में समय खराब ना करें। तरक्की पाने के लिए अपने स्वभाव में समझदारी लाना जरूरी है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। व्यवस्थित दिनचर्या रखें तथा एक्सरसाइज, योग आदि नियमित करें। भाग्यशाली रंग- हरा



मकर राशि- व्यक्तिगत तथा आर्थिक मामलों में अपने नजदीकी मित्रों तथा परिवार के लोगों के साथ सलाह जरूर लें। अपने अहंकार पर काबू रखें। व्यवसाय में आपके नेतृत्व और प्रबंधन द्वारा सभी कार्य सही तरीके से व्यवस्थित रहेंगे सिर्फ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। प्रेम प्रसंगों में भी नजदीकियां बनी रहेंगी। भाग्यशाली रंग- नारंगी



कुंभ राशि- प्रतिष्ठित लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। समय के अनुसार खुद को भी बदलने की कोशिश करें इससे परेशानियां जल्दी हल होंगी। सोशल गतिविधियों में आपका योगदान बना रहेगा। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कुछ नुकसान होने की भी स्थिति बन रही है। बड़े अधि कारियों का सहयोग भी मिलेगा। भाग्यशाली रंग- हरा



मीन राशि- आपका कर्म प्रधान होना आपके भाग्य को मजबूत कर रहा है। धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजन में अपना योगदान देने से हार्दिक खुशी मिलेगी। मेहनत करने पर ही भाग्य साथ देगा। छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को अनदेखा ही रखें। स्त्री वर्ग को अपने करियर से संबंधित विशेष सफलता मिलने वाली है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय सफल रहेंगे। भाग्यशाली रंग- हरा

हिमालय का वरदान बद्री गाय का घी

SilkyaraTM

उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली बद्री गाय जिसको "कामधेनु" भी कहा जाता है,
का परंपरागत रूप से बनाया गया घी अब देहरादून में भी उपलब्ध है

A2
प्रोटीन युक्त

औषधीय
गुणों से
भरपूर

इम्युनिटी
बढ़ाने में
लाभदायक

पाचन में हल्का
और बाल विकास
में सहायक



कुमार स्वीट्स

- सहस्त्रधारा रोड, निकट क्रॉसिंग
 - धर्मपुर, निकट एलआईसी बिल्डिंग
- पर उपलब्ध है।**

fssai

22623030001586

UDYOG AADHAR
MSME

UK050061483

THE DOON HIMALAYAN AGRO FOODS

Dehradun

Lokesh Asthana - 7409782771